

विचार बिन्दु

चापलूस आपको हानि पहुंचा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। -हरिओंध

हमने संविधान के अनुच्छेद 44 को 73 वर्षों के उपरान्त भी नहीं समझा

सं

विधान सभा में निदेशक तत्वों पर बोलते हुये डा. अम्बेडकर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि निदेशक तत्वों का आशय यह है कि भविष्य में विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों ही इन तत्वों के प्रति केवल पूजीय घोषणायें बनकर ही न हर जांचें, बल्कि इन्हें कार्यपालिका तथा विधायिका के सभी कार्यों का आधार बना दिया जो इसके बाद देश में शासन के मामले में किये जायें।

निदेशक तत्वों का आशय यह है कि भविष्य में विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों ही इन तत्वों के लिए उद्देशिका में विधायिका के प्रभावी भाग हैं -न्यायीकान् के लिए डॉ. होड़, ने कहा है कि संविधान चाहता है कि उद्देशिका में विधायिका के प्रभावी भाग हैं -न्यायीकान् के लिए डॉ. होड़, ने कहा है कि संविधान के प्रभावी भाग हैं -न्यायीकान् के लिए डॉ. होड़, ने कहा है कि संविधान का लक्ष्य एक ऐसे कल्याणकारी समाज का निर्माण करना है जिसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय देखा जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संविधान का लक्ष्य एक ऐसे कल्याणकारी समाज का निर्माण करना है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमारी राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राप्ति करे।

संविधान उद्देशिका में देश के लोगों ने बचन दिया है कि राज्य सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय देखा जाएगा। उच्चतम न्याय देने के कारण वह उल्लेख भाग 4 में। यह प्रश्न यह है कि क्या अनुच्छेद 37 के आधार पर राज्य न्याय देने से मना कर सकता है? उत्तर होगा नहीं अर्थात् राज्य कर्तव्य व जनता के अधिकारों में बाधाएं खो नहीं कर सकता।

हम यदि इन अधिकारों के कर्तव्यों की समालोचना करें तो 72 वर्ष की आजादी के बाद भी अनुच्छेद 44 को लागू नहीं करना, राज्य की उदासीनता ही कही जायेगी।

सन 1966 की राजनीतिक संधि भी यही निर्देशक तत्वों में आता है कि तीनों प्रकार के न्याय जनता को मिलने चाहिये। यह भी स्पष्ट हो चुका है मूल अधिकार व नीति निदेशक तत्वों में नागरिकों के अधिकार व राज्य के कर्तव्य ही है ये सब मानव अधिकार हैं। अतः प्रवर्णनशील हैं और एक देश एक कानून के सिद्धान्त को मानने हुए समान नागरिक संहिता लागू करना राज्य का दायित्व है।

संविधान का प्रारूपण समिति ने बचाया है जिसके अध्यक्ष डा. अम्बेडकर थे। इसे 26.1.1950 को लागू किया। समान नागरिक संहिता का उल्लेख नहीं करता है कि तीनों प्रकार के न्याय जनता को पर बहस होने के बाद अनुच्छेद 44 को साथ अनुच्छेद 37 के साथ भारत का संविधान बना। अनुच्छेद 44 में कहा गया, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होगी। इसके असिद्धते के बावजूद अब प्रम करना, अर्थात् है। अतः जनता की राय जानना चाहिया नहीं है। हम संविधान को पुनः नहीं लिख सकते।

अनुच्छेद 44 संविधान का अधिन अंग है। संविधान का संसोधन अनुच्छेद 368 के अनुधार होगा किंतु संविधान के अधिक प्रबलाधार (Features) को संसोधित किया जा सकता। अनुच्छेद 44 का संसोधन नहीं हो सकता। इसे संविधान सभा में बहस के उपरान्त पारित किया जाए और 26.1.1950 से इसी रूप में संविधान का भाग है। सुधीरी कोटे के समाच कहि रित याकाया ये थे सह हो चुके हैं जिनमें एक ही प्रश्न मूर्सिलम भाईयों की ओर से उठाया गया था कि अनुच्छेद 44 अनुच्छेद 37 के कारण प्रवर्तनीय नहीं है। मूर्सिलम पक्ष द्वारा यह आवाज उठाई गई कि समान नागरिक संहिता उनके धर्म, कुरान व शरियत के विरुद्ध है। अतः उन्हें मानव नहीं हैं। मूर्सिलम भाईयों का यह भी कहना है कि अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 25 तक उक्त विवाहों में हस्ताक्षर हो जाएं। आजादी से पूर्व अंग्रेजों के काल में समान नागरिक संहिता जैसा कानून नहीं था। अखण्ड भारत के समय जब सिन्ध भारत का अंग था, उस समय वहां मूसलमानों पर हिन्दू सम्बेशन एकत्र लागू था।

26.1.1950 के बाद मूर्सिलम भाईयों ने अनुच्छेद 44 को संसोधित करने अथवा समाप्त करने के हेतु काइ कार्यालयों सुधीरी कोटे में आनी की समान नागरिक संहिता के विषयों में तत्त्वाक, विवाह, निवार्ग, भूत्वाक और विवाह के विषय आते हैं।

ट्रिप्पल ताला के विषय पर जो कोटे ने उसे संविधान के विरुद्ध माना है और मूसलमानों ने इसको शरियत के अनुसार भारतकर धर्म में दखल करा है। इस केस में अनुच्छेद 25 पर विशद विवेद है।

संविधान चाहता है कि उद्देशिका में निर्धारित लोकतंत्रात्मक कल्याणकारी राज्य के आदर्शों को प्राप्त किया जावे। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संविधान का लक्ष्य एक ऐसे कल्याणकारी समाज का निर्माण करना है जो आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राप्ति करे।

सभी संस्थाओं को अनुप्राप्ति करे।

मूसलम भाईयों कोटे ने स्पष्ट किया है कि सभ्य समाज में विवरुद्ध हो जाएगा।

भारतीय दण्ड संहिता द्वारा मूसलमानों के दण्ड के कानून में दखल किया है। मूसलम कानून में (शरीर) चोरी करने वाले व्यक्ति को हाथ कानने की सजा है जो आर्थिक भारतीय दण्ड संहिता में जेल की सजा है। अतः यह विवरुद्ध हो जाएगा कि अधियुक्त से यह पूछा जावे कि उसे सजा भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार द्वारा यह धर्म (शरीर) के अनुसार।

सन 1985 में सुधीरी कोटे ने शाहबानों के केस में श्रीमती जोड़न डेंग के विवाहदार में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात की है और अनुच्छेद 25 पर विशद विवेद है।

देश सेक्युरिटी के लिए देशों में देशों के लिए देश के लिए देश में यह समान नागरिक संहिता लागू है।

हर धर्म, जीवि के लिए यह कानून है, कई मूसलम देशों में भी यह लागू है। बंगलादेश, पाकिस्तान तो कभी भारत के ही अंग थे वहां भी यह लागू है। इससे पुरुष पर महिला दोनों को तत्त्वाक का अधिकार मिलता है। शादी की उम्र बढ़ी जीवों, जिसके कारण महिला शादी से पूर्व जेवजे हो सकती समान नागरिक संहिता लागू होने से ऐसे सभी समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगा। आजादी से पूर्व अंग्रेजों के कानूनों का सलांकरण होगा और विवाहों में समझौता हो सकेगा बहुविवाह रुकेगा।

विधि आयोग ने 31.8.2018 में फैसिली कानून में सुधार के हेतु एक Consultation Paper भेजा था। विधि आयोग ने अपनी अधियुक्त सेवों को अधिकार व अधिकार अपनाएं रखा था। अतः विधि आयोग के अध्यक्ष ने अलग-अलग विवाह अंदर विवाह के अधिकार किये हैं। पूर्व मूर्स्य न्यायाधीश विधि आयोग के चेयरमैन जगेंद्र गडबरन ने विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कहा था, 'अनुच्छेद 44 को लागू न करना भारतीय डेमोक्रेसी की असफलता है'। जिससे डाग्स भागला ने कहा कि 'अनुच्छेद 44 को बाध्यकारी मानना चाहिये'।

देश सेक्युरिटी के लिए चुनाव जीतने के लिए विवाह अंतर्वर्ती विवाह के अधिकारों को अपनावनी भेजी है। इसके अंतर्वर्ती विवाह के अधिकारों की शुरूआत की थी। अतः यह कानून ही नहीं है। अनुच्छेद 25 पर विशद विवेद है।

Member Secretary, Law Commission of India, 4th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi 110003

लों कीमीशन ने व्यक्तिगत सुनवाई के लिये भी लिखा था।

यहां यह लिखान सभी चीजों होगा कि द्वितीय विधि कीमीशन पुनः सुनवाई पूर्वी होगी। Formulation of a Uniform Civil Code (UCC) is neither necessary nor desirable at this stage।

लों कीमीशन की दोनों रिपोर्टेस (Reports) ने रेफरेंस के अनुरूप है और न आदेश है। उनकी इहानु का कोई आधार भी नहीं है। वह अवैध व अधिकार अप्रवाहन किये हैं। ही पूर्व मूर्स्य के लिए विवाह के अधिकारों को अप्रवाहन किया जाता है। अनुच्छेद 44 को पारित किया जाता है अतः यह कहना कि यूरोपीसी की न तो आवश्यकता है और न कोई अधिकार।

इत्तहाद-ए-मूलत को अधिकार जीतने के लिए विवाह अंतर्वर्ती विवाह अंतर्वर्ती विवाह की अधिकार अप्रवाहन करना चाहिये। अतः यह कानून ही है। इसके अंतर्वर्ती विवाह के अधिकारों की शुरूआत हो जाएगी।

लेकिन ने समान नागरिक संहिता पर यात्रा करा रखी है। अतः यह कानून ही है। अनुच्छेद 25 पर विशद विवेद है।

लेकिन का लिये यह कानून है, कई मूसलम देशों में भी यह लागू है। बंगलादेश, पाकिस्तान तो कभी भारत के ही अंग थे वहां भी यह लागू है। इससे पुरुष पर महिला दोनों को तत्त्वाक का अधिकार मिलता है। शादी की उम्र बढ़ी जीवों, जिसके कारण महिला शादी से पूर्व जेवजे हो सकती होती है। अतः यह कानून ही है। अनुच्छेद 25 पर विशद विवेद है।

लेकिन का लिये यह कानून है, कई मूसलम देशों में भी यह लागू है। बंगलादेश, पाकिस्तान तो कभी भारत के ही अंग थे वहां भी यह लागू है। इससे पुरुष पर महिला दोनों को तत्त्वाक का अधिकार मिलता है। शादी की उम्र बढ़ी जीवों, जिसके कारण महिला शादी से पूर्व जेवजे हो सकती होती है। अतः यह कानून ही है। अनुच्छेद 25 पर विशद विवेद है।

लेकिन का लिये यह कानून है, कई मूसलम देशों में भी यह लागू है। बंगलादेश, पाकिस्तान

